इस सारी स्थिति पर सिविल एविएशन और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों को मिलकर सोचना चाहिए, संभव है, द्वारिका के किसी छोटे अस्पताल या क्लीनिक में भी अगर उन्हें ले जाया जाता, तो शायद उनकी जान बच जाती। मेरा अनुरोध है कि संबंधित मंत्रालय इस पर ध्यान दें, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

श्री शाहिद सिद्दीकी (उत्तर प्रदेश): सर, मैं इस विशेष उल्लेख का समर्थन करता हूं।

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): सर, मैं भी इस विशेष उल्लेख का समर्थन करता हूं।

श्री मतिलाल सरकार (त्रिपुरा): सर, मैं इस विशेष उल्लेख का समर्थन करता हूं।

श्री बनवारी लाल कंछल (उत्तर प्रदेश): सर, मैं इस विशेष उल्लेख का समर्थन करता हूं।

Need to promote Guwahati Airport as a regional connecting hub to South East Asian Nations

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would draw the kind attention of the Government to the Guwahati Airport to be a regional hub for the air connectivity of the NER in terms of the Prime Minister's package of 1996. The Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport, Guwahati is yet to be equipped for landing of Jumbo Aircraft due to inadequacy of requisite runway. Now only one flight is scheduled from Gopinath Bordoloi International Airport, Guwahati to Bangkok and people are not interested in North-Eastern Region for travelling to Bangkok only. Unless a full-fledged runway for landing of jumbo international aircraft is developed there seems to be no demand from other airlines. Such demand for international flights to various destinations in South East Asia like Tokyo, Singapore, etc. would come only after developing full facilities of an internatieal airport like customs and immigration counter of international standards. I, therefore, urge on upon the Government to reiterate the earlier decision for making Guwahati Airport as the regional hub for the North Eastern Region and create all facilities for customs and immigration along with requisite infrastructure for cargo handling, aero bridges, etc., in a separate international terminal building to encourage export activities from the region in view of 'Look East Policy'. Thank you.

Concern over the delay in Publication of the Book 'People of India'

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, दो दशक पहले केन्द्र सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्वावधान में एक शोध परियोजना की शुरूआत की थी। 'पीपुल ऑफ इंडिया' नाम की इस इस परियोजना का उद्देश्य किसी राज्य-विशेष में रह रहे समुदायों/जातियों की पहचान करना था। इस शोध अध्ययन के लिए डा॰ कुमार सुरेश सिंह को परियोजना का प्रभारी बनाया गया। उन्हें पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार भी सौंपा गया। डा॰ सिंह की टीम ने अथक परिश्रम और गहन अध्ययन से देश के प्रत्येक प्रदेश में रहने वाली जातियों का विस्तृत लेखा-जोखा तैयार किया। देश के लगभग सभी राज्यों के अध्ययन खंडों का प्रकाशन पिछले 10-12 वर्षों के दौरान किया जा चुका है, लेकिन बिहार खंड का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है।

महोदय, उल्लेखनीय है कि बिहार खंड के सम्पादन का जिम्मा प्रो॰ सुरेन्द्र गोपाल और प्रो॰ हेतुकर झा को सौंपा गया था। इन लोगों ने काफी पहले ही पुस्तक का सम्पादन-कार्य पूरा कर इसकी अंतिम पांडुलिपि डा॰ सुरेश सिंह को भेज दी थी। डा॰ सिंह ने पांडुलिपि देखने के बाद उसे अध्ययन-श्रृंखला के प्रकाशक को भेज दिया था। वर्ष 2004 में प्रकाशक ने प्रो॰ गोपाल और प्रो॰ झा को सूचना दी थी कि वह बिहार खंड का प्रकाशन करने जा रहा है। प्रकाशक ने जो पांडुलिपि के पास भेजी थी, उसमें पुन: आवश्यक संशोधन कर के दिसम्बर, 2005 में प्रकाशक के पास भेज दिया गया था। लेकिन खेद की बात है कि दो वर्ष बीत जाने के बाद भी बिहार खंड का प्रकाशन अब तक नहीं किया गया है। प्रकाशक ने खंड के सम्पादकों को भी विलम्ब के कारणों की जानकारी नहीं दी है।

अत: आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि 'पीपुल ऑफ् इंडिया' के बिहार खंड का प्रकाशन जल्द-से-जल्द सुनिश्चित किया जाये।

Need to sanction an economic package for the Sugar Industry and take measures *for immediate payment of balance amount to the Sugarcane Growers in Uttar* Pradesh

श्री अमीर आलम खान (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि व किसानों की दुर्दशा के प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं। किसान खेती-बाड़ी से हाथ खड़े करने लगे हैं, क्योंकि खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। सरकार की अनदेखी व ढुलमुल रवैयों के कारण किसान सांसत में है। कर्ज के बोझ तले किसान आत्महत्या करने को बाध्य है।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के बकाया भुगतान न होने से किसानों की कमर टूट गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों पर मार दो-तरफा है, एक तरफ तो उनका बकाया भुगतान है और दूसरी तरफ गन्ने का वाजिब मूल्य न मिलना है। अगर सन् 1970 के मूल्यों से गन्ने की तुलना की जाए तो गन्ने का मूल्य केवल 5-6 गुना ही बढ़ा है जबकि अन्य वस्तुओं जैसे डीजल, *ईंट, सीमेंट, मजदूरी आदि के दाम 20-25 गुना बढ़ गए हैं।*

महोदय, गन्ने पर ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था निर्भर है। इस से बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि उत्तर भारत की खाद्य टोकरी,पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, आज पाई-पाई को मोहताज हैं। अनेक जिम्मेदारियों को ओढ़े यह किसान बस यही राह देख रहा है कि किसी तरह उसके गन्ने के बकाया का भुगतान हो जाए।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करे तथा अविलम्ब हस्तक्षेप कर के चीनी मिलों द्वारा गन्ने का बकाया भुगतान किसानों को कराए तथा गन्ने का बढ़ा हुआ मूल्य भी घोषित करे जिससे गन्ना किसानों के हितों की रक्षा हो सके तथा खेती को आर्थिक रूप से लाभदायक बनाया जा सके।

Concern over the misrable condition of Tribals of Dangs in Gujarat

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL (Gujarat): Sir, a recent report by Shri A.P. Ravani, Former Chief Justice, Rajasthan High Court which is published by 'Gujarat Foundation for Development Alternatives' Vadodara, Gujarat State has proved that Bhil Rajas who fought British and Gaekwad Army, before 1947, are in rags today and get annual political pension of Rs. 2/- to Rs. 1000/- from present rulers. The Dangs did not form part of British India. They have never been conquered or annexed by the Government nor they have been ceded.

In view of the above, hon. Home Minister may clarify the following issues:—

(i) whether any merger agreement was taken from the Tribal Chief of Dangs?

(ii) If no, why the same was not taken?

(iii) Is it true that the Tribal Chiefs had passed resolution objecting to the merger with the Bombay Province?

(iv) When was the question of rights and privileges of the Chief and Naiks decided?

(v) How the Chiefs were made political pensioners instead of ex-rulers?

(vi) Who collects the land revenue in Dangs?

(vii) What is the total amount collected till 31.03.2007 towards land revenue?

(viii) How much from the above collection is paid to Dang Tribal Chiefs?